University in News on 02 February 2022

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5 & 6

लविवि : सहयुक्त कॉलेजों को फिर मिला आश्वासन

फीस में कमी के लिए कॉलेज प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रार से की मुलाकात, रजिस्ट्रार ने कहा-अभी आचार संहिता के कारण नहीं किया जा सकता

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से नए जुड़े चार जिलों रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई व सीतापुर के कॉलेजों को एक बार फिर कोरे आश्वासन से काम चलाना पड़ेगा। मंगलवार को कॉलेज प्रतिनिधियों ने दिसंबर में मिले आश्वासन के अनुसार परीक्षा शुल्क में 250 रुपये कम करने की मांग उठाई। वहीं, विवि प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए इसे आगे कम करने का आश्वासन दिया।

कॉलेज प्रतिनिधियों ने मुद्दों को लेकर बातचीत की। अमर उजाला

लविवि और कानपुर विवि के परीक्षा शुल्क में काफी अंतर है। यही वजह रही कि कानपुर विवि को छोड़कर लविवि से संबद्ध कॉलेज शुरुआत से इसमें कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। विवि प्रशासन ने पहले 500 रुपये पंजीकरण शुल्क व 500 रुपये परीक्षा शुल्क कम किया था, किंतु कॉलेज इस पर तैयार नहीं थे।

नौ दिसंबर को रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार से हुई वार्ता में परीक्षा शुल्क 250 रुपये और कम करने की बात हुई थी। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं और परीक्षा फार्म भी जमा होने लगे। इस क्रम में उक्त जिलों के कॉलेज प्रतिनिधि मंगलवार को फिर रजिस्ट्रार से मिले। हालांकि उन्होंने आचार संहिता का हवाला देते हुए इसमें अभी कमी करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि अगले सेमेस्टर में इसे समायोजित किया जा सकता है। वहीं रजिस्ट्रार डॉ. सिंह ने कहा कि कॉलेज अपनी कुछ मांग लेकर आए थे, जिस पर वार्ता हुई है। कॉलेज व छात्रहित में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

एमबीए-एमएससी का रिजल्ट जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय व सहयुक्त महाविद्यालयों के दिसंबर में हुई एमबीए व एमएससी के नियमित व बैक पेपर के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी के अनुसार परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (माई सिटी रिपोर्टर)

यूजी का नया अध्यादेश पास

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस सत्र 2021-22 से स्नातक में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को प्रभावी बनाया गया है। इसी क्रम में विद्या परिषद के बाद मंगलवार को कार्य परिषद से भी इसे बाईसर्कुलेशन पास कर दिया गया है। रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अब इसे राजभवन भेजा जाएगा। जहां से हरी झंडी मिलने पर यह पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। (माई सिटी रिपोर्टर)

31 विद्यार्थियों को मिला प्लेसमेंट

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के एमबीए के 31 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। इन विद्यार्थियों का चयन आईसीआईसीआई बैंक में 4.20 लाख सालाना के पैकेज पर हुआ है। निदेशक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल डॉ. संजय मेधावी के अनुसार चयनितों में आयुषी गुप्ता, मुस्कान सिंह, अर्पिता गुप्ता, सौम्या मिश्रा, हरदेव सिंह, शिल्पी, अरीबा नैय्यर जैदी आदि हैं। (माई सिटी रिपोर्टर)

डिजिटलीकरण से होगा चौतरफा विकास

इस बार के केंद्रीय बजट में सबसे खास यह है कि डिजिटलीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा, कृषि, रक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण कर डिजिटली मनी पर कार्ययोजना तैयार कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा और कृषि पर खास फोकस है। डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्कूलों की कक्षाओं में टीवी उपलब्ध कराने के साथ 200 भाषाओं में शैक्षणिक चैनल लॉन्च करने की योजना है। अब तक जो कहा जाता रहा है कि ऐसे छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है, जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के संसाधन नहीं है वे भी अब ऑनलाइन पढ़ाई से अछूते नहीं रहेंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की योजना लाकर डिजिटल टीचिंग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। शिक्षा ग्लोबल होने जा रही है। इससे उत्कृष्ट पढ़ाई का लाभ छात्रों को मिलेगा। प्राकृतिक खेती को लेकर क्रांतिकारी सुधार लाने की योजना है। गंगा बेल्ट के दोनों तरफ प्राकृतिक खेती करने की योजना है। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट होगा। इससे देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तो वे खेती में पूंजी भी लगाएंगे और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जोर दिया गया है। इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, इससे युवाओं को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्रीन जॉब योजना को लाए जाने की बात कही जा रही है।

- प्रो. मनोज कुमार अग्रवाल
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय

HINDUSTAN PAGE 2 & 5

बजट में कई अभिनव प्रयोग भी किए गए जिससे अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर किया जा सके

तकनीक और आधारभूत ढांचे से लक्ष्य साधने का प्रयास

त्वरित टिप्पणी

- प्रो. एमके अग्रवाल
हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2022-23 का बजट फिर से पारम्परिक न होकर पिछले प्रयासों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में नव ऊर्जा का संचार करता हुआ नजर आ रहा है। बजट में कई अभिनव प्रयोग भी किए जा रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को समयानुकूल आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके जो समावेशी भी हो। बजट प्रगतिशील एवं विस्तारित करने के लिए पूंजीगत व्यय काफी महत्व दिया गया है।

कोरोना संकट के बावजूद बजट घाटे को काफी नियंत्रित कर दिया गया है जो कि इस वर्ष 6.9% है और अगले वर्ष 2022-23 यह घटकर 6.4 होने का अनुमान है। दरअसल, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को हैंडल किया गया है। उसने कोरोना संकट की चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में रिकवरी बहुत तीव्र हो रही है। जिसके कारण वर्तमान आर्थिक विकास दर 9.2%होने का अनुमान है। यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का सूचक है। इसी से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी व स्वदेशी अर्थव्यवस्था को प्रगाढ़ करने पर बल दिया जा रहा है।

यद्यपि लघु एवं मझोले उद्योगों व व्यापार को सस्ते ऋण की विशिष्ट सुविधा एक साथ बढ़ाने से इस क्षेत्र को फायदा होगा। यही नहीं डिजिटल नवाचार से ग्रामीण विद्यार्थियों की हर कक्षा के छात्रों का नया चैनल शुरू किया जाएगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए ई-लैब व ई-विश्वविद्यालय की स्थापना से नए रोजगार का सृजन होगा।

डिजिटल तकनीक डालेगी दीर्घकालिक प्रभाव

प्रधानमंत्री आवास व नल से जल योजना को और तेज किया जा रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल करेंसी ओर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार सम्पूर्णता में देखते हैं तो डिजिटल तकनीक कृषि क्षेत्र से लेकर पढ़ाई तथा डिजिटल करेंसी एवं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर अपना दीर्घकालिक प्रभाव डालेगी। जिससे आय व रोजगार समावेशी हो सकेगा।

समावेशी बजट में हर वर्ग का ध्यान

1 भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समावेशी बजट पेश किया है। चाहे युवा वर्ग हो, नौकरीपेशा या किसान और व्यापारी वर्ग समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। वर्तमान समय में देश बेराजगारी की समस्या से जूझ रहा है। सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा सेक्टर में 5.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। जिससे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ बेराजगारों को काम देने में भी मदद मिलेगी।

साथ ही 60 लाख नई नौकरियां, रोजगार का प्रावधान किया गया है।

प्रो. अवधेश कुमार, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

इसके साथ ही किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के रुप में रखा गया है। जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकेगा।

कोविड महामारी से निपटने के लिए हास्पिटैलिटी सेक्टर को 60 हजार करोड़ रुपये ग्रांटेड फ्री कर्ज देने का प्रावधान है। जिससे इस सेक्टर में मजबूती आएगी और भविष्य में किसी भी महामारी में सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा। मध्यम वर्ग की आय पर कर का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाया गया। साथ ही डिजीटल करंसी के माध्यम से भारत को डिजीटल भारत बनाने की तरफ एक साहसिक कदम भी उठाया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष ऋण सुविधा मार्च 2023 के लिए बढाई गई है।

बजट औसत है। अगर निराशाजनक न कहें तो उत्साह भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं मिला। कोविड काल में शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रो. रोली मिश्रा
अर्थशास्त्र विभाग, एलयू

i-NEXT PAGE 2 & 5

सभी की फीस कर दी जाएगी समायोजित

वीसी से मिला चारों जिलों का प्रतिनिधि

एलयू ने दो बार में 750 रुपए फीस कम करने पर सहमति दी थी, पर एलयू ने जुलाई में पांच सौ रुपए छुट का आदेश दिया.

LUCKNOW (1 Feb, inext): , एलयू प्रशासन ने चार नए जुड़े जिलों के कॉलेजों को सेमेस्टर एग्जाम फीस में राहत देने का ऐलान तो किया लेकिन इसका आदेश जारी नहीं किया. ऐसे में एलयू से जुड़े चारों नए जिलों के कॉलेजों को स्टूडेंट्स से सेमेस्टर एग्जाम फीस को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को इन चारों जिलों के करीब 70 से अधिक डिग्री कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने वीसी प्रो. आलोक कुमार राय से मुलाकात की. प्रतिनिधि मंडल ने वीसी से दिसंबर में तय हुए सेमेस्टर एग्जाम की फीस में निर्धारित छुट देने की बात कही. जिस पर वीसी ने इस संबंध ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि इस छुट को आगे समायोजित कर दिया जाएगा. अभी जो छुट दिया गया है, उसी के आधार पर कॉलेज फीस एलयू को जमा करा दें.

31 तक फीस जमा करानी थी

एलयू की ओर से सभी चारों जोड़े गए नए जिलों को 31 जनवरी तक एग्जाम फीस यूनिवर्सिटी के पास जमा कराने का निर्देश दिया था. जिसके बाद भी चारों जिलों से सैकड़ो कॉलेजों ने अभी तक एग्जाम फीस यूनिवर्सिटी में नहीं जमा कराया हैं. उनका कहना है कि एलयू ने दो बार में 750 रुपए फीस कम करने पर सहमति प्रदान किया था. पर एलयू ने जुलाई में दिए गए पांच सौ रुपए छुट का आदेश तो जारी कर दिया. पर दिसंबर में जो 250 रुपए और कम करने पर सहमति बनी थी. उनका निर्देश नहीं जारी किया है. जिस कारण निर्धारित डेट बीतने के बाद भी कई कॉलेजों ने अभी तक एग्जाम फीस नहीं जमा किया है.

तकनीकी संग अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की योजना

LUCKNOW (1 Feb, inext): केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 2022-23 तक बजट अमृत काल की एक डिजिटल बुनियाद रखती हुई नजर आती हैं. इसके अंतर्गत डिजिटल रुपए से लेकर किसान के लिए ड्रोन तकनीक तथा डिजिटल तकनीक से होते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेष चैनल चलाने की बात कहीं गई है. इसके तहत युवाओं के कौशल विकास तथा डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत को नया आयाम देंगे.

प्रो. एमके अग्रवाल

कृषि विकास के कई कार्यक्रम

कृषि विकास के लिए कई कार्यक्रम हैं, जिसमें गंगा किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है. इसी प्रकार छोटे व मझोले उद्योग एवं सेवा इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं में एक वर्ष के लिए सस्ते ऋण सुविधा को विस्तारित किया गया है. सबके लिए मकान व नल से जल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है. इस बजट में मध्यम वर्ग को व्यक्तिगत आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है. लेकिन कोई नया कर की नहीं लगाया गया है. राज्यों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनके बजट घाटे में वृद्धि की अनुमति देने के साथ ही एक लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण 50 सालों के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु देने की बात कही गई है. यह नया प्रयोग है. इसी के साथ ही प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत सात इंजन वाले आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया. जिससे भारत स्वावलम्बी हो सके तथा तेजी से विश्व पटल पर अपना स्थान सुनिश्चित कर सके. कुल मिलाकर यह बजट में नई तकनीकी के साथ अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की योजना है.

RASHTRIAYA SAHARA PAGE 2

डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा आधारभूत संरचना पर जोर-प्रो.एमके अग्रवाल

लखनऊ। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत 2022- 23 बजट अमृत काल की एक डिजिटल बुनियाद रखती हुई नजर आती है। इसके अंतर्गत डिजिटल रुपए से लेकर किसानों के लिए ड्रोन तकनीक द्वारा तथा डिजिटल तकनीक से होते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेष चैनल चलाने की बात कही गई है इसके तहत युवाओं के कौशल विकास तथा डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करके नया आयाम देंगे।

कृषि विकास के लिए नरेंद्र मोदी बजट में कई कार्यक्रम है, जिनमें गंगा के किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसी प्रकार छोटे और मझोले उद्योग और सेवा इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं है इसके साथ ही एक वर्ष के लिए सस्ते ऋण सुविधा को विस्तारित किया गया ᳐ सबके लिए सस्ते मकान और नल में जल और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है।

यदि इस बजट मे मध्यम वर्ग को व्यक्तिगत आयकर में कोई राहत नहीं दी गयी है लेकिन कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है जबकि संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए पूंजीगत परिव्यय में वर्तमान वर्ष में काफी बढ़ोतरी की गयी है और अगले वर्ष में 2022-23 में 35 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है जबकि घारे को कंट्रोल में रखा गया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्यों अर्थव्यवस्था में तीव्र बढ़ोतरी के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है। राज्यों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनके बजट घाटे में अनुमति देने के साथ 5 लाख करोड़ का ब्याजयुक्त ऋण अगले 50 वर्षो के लिए आधारभूत कलश के विकास देने की बात कही बाई है। यह नया प्रयोग है। इसके साथ हो प्रधानमंत्री गति शक्ति के अन्तर्गत सात इंजन वाले आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भारत स्वावलंबी हो सके।

कुल मिलाकर यह बजट नई चुनौतियां के साथ-साथ नई तकनीक के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की योजना है साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा व उत्पादन लागत कम करके आगे बढ़ने की रणनीति नजर आती है। ऐसे में तीव्र विकास की उम्मीद करना सम्भव प्रतीत होता है।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं)

NBT PAGE 4

डिजिटल टेक्नॉलजी और आधारभूत संरचना पर जोर

केंद्र सरकार का बजट एक डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में बुनियाद रखता नजर आ रहा है। डिजिटल मनी से लेकर किसानों को तकनीक से जोड़ते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जरूरत के मुताबिक विशेष चैनल की बात कही गई है। युवाओं के कौशल विकास तथा डिजिटल युनिवर्सिटी भी इस क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को एक नया आयाम देगा।

कृषि विकास के लिए कई कार्यक्रम हैं। इनमें गंगा किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शामिल है। इसी तरह छोटे व मंझोले उद्योग व सेवा इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं हैं। इसमें सस्ते ऋण सुविधा को विस्तारित किया गया है। सबके लिए मकान व नल से जल व स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। ऐसे में बजट आमजन पर केंद्रित दिखता है। गरीबों का भी खास ख्याल रखा गया है।

बजट की बारीकियां

प्रो. एमके अग्रवाल,
हेड, अर्थशास्त्र विभाग, एलयू

मध्यम वर्ग को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है लेकिन कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए भी पूंजीगत परिव्यय में काफी बढ़ोतरी की गई है। राज्यों को भी प्रोत्साहित करने के लिए बजट घाटे में वृद्धि की अनुमति देने के साथ ही एक लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण 50 सालों के लिए देना आधारभूत संरचना के विकास को मदद देने में कारगर साबित होगा। सहकारी समितियों के लिए की गई घोषणा भी एक दूरगामी परिणाम ला सकती हैं लेकिन अगर इससे आम आदमी को सीधे जोड़ा जाए।

कुल मिलाकर बजट नई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीक के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला दिखता है। पर्यावरणीय सुरक्षा व उत्पादन लागत कम कर आगे बढ़ने की रणनीति नजर आती है। ऐसे में तीव्र विकास की उम्मीद करना संभव लग रहा है।

AMRIT VICHAR PAGE 5

25 वर्ष के रोड मैप में आम आदमी के हाथ खाली

आम बजट पर अर्थशास्त्री प्रो. अरविन्द मोहन की राय, ग्रामीण और मानव विकास के लिए कुछ नहीं किया गया

अमृत विचार, लखनऊ

आम बजट में 25 साल का रोडमैप भले ही तैयार किया गया हो लेकिन इसमें आम आदमी के हाथ खाली है। 25 साल में हिन्दुस्तान विकास गाथा तैयार की गई लेकिन इसमें देश का आम आदमी दरकिनार कर दिया गया है। उसके लिए न तो कोई रोजगार की व्यवस्था की गई और न ही आय बढ़ाने पर ध्यान।

यह बात लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रो. अरविन्द मोहन ने कही। उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामीण और मानव विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। ग्रामीण विकास के तहत कृषि, लघु व कुटिर उद्योग और मानव में स्वास्थ्य व शिक्षा के विषय में कोई बात नहीं की गई। आम बजट जो वर्ष 1991 में सुधार की बात की गई थी, हम आज भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। इस बजट से आशा थी कि पिछले 10 सालों से जो विकास की बात जा रही है, उसे पूरा किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली चुनौती थी कि देश के 140 करोड़ आम लोगों को विकास यात्रा से जोड़ा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चुनौती पहले नोट बंदी और दूसरा कोविड के चलते असंगठित क्षेत्र लगभग खत्म हो गया। उससे निचला, निचला मध्यम और मध्यम वर्ग के पास रोजगार था, खत्म हो गया। इनकी आय का स्रोत खत्म या चौथाई हो गई। इस तबके को सहायता की अत्याधिक जरूरत थी, हम अभी महामारी काल में है, ऐसे में बिल्कुल दरकिनार कर दिया।

बड़े औद्योगिक घरानों को दिया फायदा

प्रो. अरविन्द मोहन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जो पिछले 50 साल से बैसाखी पर दे रखा था, उसके लिए कुछ नही किया। छोटे किसान, मजूदरों, निचले, निचले मध्यम और मध्यम वर्ग के लिए कहीं कुछ नही किया। इनको बजट में किसी प्रकार से सहयोग देने की कोशिश नहीं की गई लेकिन बड़े परिवार और औद्योगिक घरानों को दीर्घकालीन आयकर पूंजीगत आय पर सरचार्ज कम कर दिया। ये भी तब किया गया जब ओक्सफॉम की रिपोर्ट के अनुसार कोविडकाल में जो भी सरकार ने किया। सरकार का दावा है कि 27 लाख करोड़ का बजट खर्च किया। यह सब देश के 100 से कम परिवारों व बड़े औद्योगिक घराने पास चला गया। उम्मीद थी कि इन पर एक अतिरिक्त कर लगाकर अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा लेकिन इसके पलट उन्हें छूट दी गई। जिसे जरूरत थी उनके लिए कुछ नहीं किया, जिनको जरूरत नहीं थी उनके लिए कर कम कर दिया।

क्रिप्टो करेंसी को लेकर असमंजस की स्थिति

सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसदी का कर लगाया है और डिजिटल करेंसी पर एक फीसदी का टीडीएस लगाया गया। इस पर प्रो. मोहन असमंजस की स्थिति में है। वह स्पष्ट नहीं बता पा रहे है कि क्या बिटक्वॉइन जैसी को सरकार ने आप्रत्यक्ष रूप से वैध किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी करेंसी का कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

PIONEER PAGE 4

शुल्क में राहत देने की मांग को लेकर कालेजो ने की कुलपति से मुलाकात

लखनऊ। सीमा विस्तार के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े कर जिले रायबरेलीए हरदोईए सीतापुरए लखीमपुर खीरी के कॉलेज संचालकों ने मंगलवार को शुल्क कम करने को लेकर विवि के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कुलपति ने कॉलेजों को आगे की फीस में एडजस्ट करने का आश्वासन दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चार नए जुड़े जिलों के कॉलेजों को सेमेस्टर परीक्षा शुल्क में राहत देने का ऐलान तो किया लेकिन इसका आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में एलयू से जुड़े चारों नए जिलों के कॉलेजों को स्टूडेंट्स से सेमेस्टर परीक्षा शुल्क को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। इसी कड़ी में आज इन चारों जिलों के करीब 70 से अधिक डिग्री कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने कुलपति प्रो आलोक कुमार राय से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से दिसंबर में तय हुए सेमेस्टर एग्जाम की फीस में निर्धारित छुट देने की बात कही। जिस पर कुलपति ने इस संबंध ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि इस छुट को आगे समायोजित कर दिया जाएगा।